>

Title: Issue regarding giving special status to different states.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदया, विशेष राज्य के दर्जे के लिए पूरे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसका एक पोलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। बिना सोचे-समझे कांग्रेस पार्टी के मंत्री, योजना विभाग के मंत्री राजीव शुक्ला साहब बयान देते हैं कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जब 2013-14 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया, उस बजट को पेश करने में उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए, पिछड़े राज्य के दर्जे के लिए वे एक कमेटी बना रहे हैं और उसके साथ एक मापदंड तय होगा कि विशेष राज्य के दर्जे का कौन-कौन सा राज्य हकदार है। अभी रघुरामराजन कमेटी बनाई गई। रघुरामराजन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और बिना उस रिपोर्ट के आए हुए मंत्री पार्लियामेंट में गलतबयानी कर रहे हैं। यह विशेषाधिकार का मामला है। चूँकि यह दूसरे सदन का मामला है इसलिए मैंने प्रिविलेज नहीं उठाया, लेकिन मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूँ, झारखंड सबसे ज़्यादा माइन्स और मिनिरल्स देता है, लेकिन हमारे जो 17 ज़िले हैं, वे इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में हैं, नक्सलाइट्स से घिरे हुए हैं। 21 ऐसे ज़िले हैं जो एस.आर.ई. में हैं। गृह मंत्रालय मानता है कि नक्सलाइट एरिया है और सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. की वहाँ जो कंपनियाँ हैं, उनको पैसा देने में राज्य का सारा पैसा चला जाता है। इसके अलावा हमारे 24 में से 23 ज़िले बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में हैं। 75 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 70 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो मालन्यूट्रीशन के शिकार हैं। 72 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ हैं जो एनीमिक हैं। हमारा कंज़म्पशन का जो लैवल है, चाहे वह बिजली का कंज़म्पशन हो, स्टील का कंज़म्पशन हो, चाहे सीमैन्ट का कंज़म्पशन हो, हम भारत सरकार के डाटा में सबसे नीचे हैं। आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा पिछड़े 12 ज़िलों की जो लिस्ट भारत सरकार ने बनाई है, वे 12 के 12 ज़िले झारखंड में हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो, लिट्रेसी रेट महिलाओं का काफी नीचे है, पुरुषों का लिट्रेसी रेट काफी नीचे है, तो कौन सा आधार है? यदि किसी एक राज्य को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो वह झारखंड को मिलना चाहिए। झारखंड को यदि राजनीतक कारणों से ये महरूम करते हैं तो यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस देश को आज हम चला रहे हैं। यदि आज मुम्बई में पैसा है, दिल्ली में पैसा है तो 50 परसेंट से ज़्यादा माइन्स और मिनिरल्स केवल झारखंड देता है जबकि रॉयल्टी के नाम पर आप हमको एक पैसा नहीं देते हैं। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं - टाटा है, बिड़ला है, जिन्दल है, वे वहाँ से माइन्स और दूसरी चीज़ें लूटकर लाती हैं। कोल इंडिया है, सेल है, डीवीसी है, उसका हैडक्वार्टर आपने कोलकाता बना दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और झारखंड को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सरकार कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे लेकिन ये केवल अलायंस की राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया :

श्रीमती ज्योति धुर्वे एवं

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के नाम श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।